नीति में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अध्याधीन-लाइसेंस की अपेक्षा के बिना कताई एकक स्थापित करने के लिये स्वतंत्र हैं।

कपड़ा मिलों की सूत उत्पादन क्षमता

4081. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :
श्री राम जेठमलानी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत कार्यरत मिलों में सूत का उत्पादन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों की सूत उत्पादन की वार्षिक स्थापित क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या इन मिलों की स्थापित क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो वर्ष 1990–91, 1991–92 और 1992–93 में कितने सूत का उत्पादन किया गया और कितने प्रतिशत उत्पादन क्षमता का उपयोग किया गया ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1991–92 के दौरान यार्न उत्पादन के संबंध में एन०टी०सी० मिलों की स्थापित क्षमता 37.34 लाख तकुए थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वर्ष 1990–91 से 1992–93 (अनन्तिम) तक की अवधि के दौरान एन०टी०सी० मिलों द्वारा निर्मित यार्न के ब्यौरे और उपयोग में लाई गई क्षमता का प्रतिशत नीचे दिया गया है:–

वर्ष	कुल यार्न उत्पादन कि०ग्रा०	क्षमता उपयोग (%)
1990–91	173.95	66.2
1991–92	159.42	60.5
1992–93 (अनन्तिम)	117.00	47.5

Area based projects for welfare of handloom weavers

4082. SHRI FARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to refer to answer to Unstarred Question 2429 given in the Rajya Sabha on the 15th March, 1993 and state;

(a) whether Government pro pose to promote area-based project specific programme for the welfare of weavers and for development of iden tified handloom products;

(b) if so, the details of such programme and the areas identified for purpose; and

(c) the number of weavers likely to be benefitted under the programme, State-wise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Yes, Sir

(b) Projects are sanctioned under Project Package Scheme on receipt of comprehensive and viable proposals from the State Governments. Such projects may have one or more of the following objectives, namely, development of a particular product benefit a particular area and benefit a particular target group. This is an on go-mg Scheme. So far under the Scheme , projects have been sanctioned in the